**ई-गवर्नेंस सम्मेलन • केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह का सवाल**

# एआई के युग में 2047 तक अफसरों की क्या भूमिका होगी?

जयपुर| केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और पीएम ऑफिस में कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को आरआईसी में चल रहे 29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन के पुरस्कार सत्र में कहा कि राजस्थान भी ई-गवर्नेंस के माध्यम से सुशासन की दिशा में अग्रणी है। इसका प्रमाण यह है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पहली पसंद राजस्थान है।

शासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब वैकल्पिक नहीं, बल्कि अनिवार्य है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि असली चुनौती सिर्फ एआई को अपनाने में नहीं, बल्कि इसे बुद्धिमानी से उपयोग करने में है, जिसमें तकनीकी प्रगति के साथ मानवीय हस्तक्षेप भी अनिवार्य है। उन्होंने बदलाव की रफ्तार को समझाते हुए वीसीआर और एसटीडी बूथ जैसी पुरानी तकनीकों का उदाहरण दिया, जो मात्र दो दशकों में गायब हो गईं। उन्होंने सवाल उठाया कि 2047 में सरकारी अधिकारियों की क्या भूमिका होगी, क्योंकि डिजिटल सिस्टम तेज गति से पारंपरिक राजकीय कार्य पद्धति को बदल रहे हैं। एआई अब केवल एक विकल्प नहीं रह गया है, बल्कि शासन का एक आवश्यक का हिस्सा बन चुका है। सार्वजनिक संस्थानों को ऐसी तकनीकों से सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता से प्रेरित है जो पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता और सेवा वितरण में सुधार करती हैं।

## जिम्मेदार-समावेशी एआई की दिशा में बढ़ रहा देश: राज्यवर्धन

राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि एक ओर जहां दुनिया एआई की चर्चा कर रही है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत "जिम्मेदार और समावेशी एआई' की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीक का उद्देश्य केवल नवाचार करना नहीं, बल्कि उसका लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाना भी है।